

विपक्ष ने बजट को बताया ‘जनविरोधी’ तो भाजपा ने गरीब, महिलाओं को समर्पित बताया

नई दिल्ली। विपक्षी दलों ने आम बजट को ‘जनविरोधी’ करार देते हुए वीरवार को कहा कि केंद्रीय बजट में भविष्य को लेकर कोई दृष्टिकोण नहीं है तथा मनरेगा सहित विभिन्न जन कल्याण योजनाओं के लिये आवंटन कम किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट पर निचले सदन में हो रही चर्चा में भाग लेते हुए विपक्ष ने अडाणी समूह से जुड़े मामले की जांच सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड) से कराने की मांग भी की। वहीं, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने गरीबों को पक्के मकान, मुफ्त राशन, रसोई गैस सहित आम लोगों के कल्याण की योजनाओं को प्रतिबद्धता के साथ बढ़ाया है और बजट का लाभ गांव, गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं सहित सभी वर्गों को मिल रहा है। चर्चा में हिस्सा लेते हुए तश्नमूल कांग्रेस के सौगत रॉय ने कहा कि इस बजट में भविष्य को लेकर कोई दृष्टिकोण नहीं है। यह अवसरवादी और जनविरोधी बजट है। रॉय ने आरोप लगाया कि कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल की



उपेक्षा कर रही है, राज्य के लिए मनरेगा की राशि जारी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि मनरेगा का पैसा तत्काल जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो भी रेल परियोजनाएं हैं उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। रॉय ने अडाणी समूह से जुड़े मामले के संदर्भ में कहा कि सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड) को इसकी जांच करनी चाहिए। वहीं, भाजपा के सुधीर गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने गरीबों को पक्के मकान, मुफ्त राशन, रसोई गैस सहित

आम लोगों के कल्याण की योजनाओं को प्रतिबद्धता के साथ बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि पोषण अभियान का ही परिणाम है कि देश एनीमिया मुक्ति की दिशा में बढ़ रहा है और बजट में कृषि क्षेत्र को पर्याप्त तवज्जो दी गई है। गुप्ता ने कहा कि सरकार गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा का प्रबंध करने के साथ नवाचार, स्टार्टअप की रणनीति लाई, जिसका लाभ देश को मिल रहा है। भाजपा सदस्य ने कहा कि अगर स्वास्थ्य क्षेत्र की ही बात करें तब इस बार बजट में इस क्षेत्र को 86,200 करोड़ रुपये दिये गए हैं जो वर्ष

आप के जैस्मीन शाह की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 15 मार्च को करेगी सुनवाई

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उपराज्यपाल (एलजी) वी.के. सक्सेना के दिल्ली संवाद और विकास आयोग (डीडीसी) के उपाध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और कार्यालय से जुड़े किसी भी विशेषाधिकार और सुविधाओं का उपयोग करने से रोकने का निर्णय करने के मामले सुनवाई के लिए 15 मार्च की तारीख तय की है। शाह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नैयर ने कहा कि पूरी शक्ति विधान सभा के पास है और नियुक्ति और हटाने की शक्ति केवल मुख्यमंत्री के पास है। ट्रांजैशनल ऑफ बिजनेस (संशोधन) नियमों का जिक्र करते हुए नायर ने कहा, मुख्यमंत्री या उनके वकीलों के संदर्भ में उपराज्यपाल को नियमों का पालन करना चाहिए। नैयर द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर ध्यान देने के बाद अदालत ने मामले में प्रतिवादियों को 6 मार्च तक लिखित प्रतुतियां दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को 15 मार्च को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन की अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। उच्च न्यायालय ने 13 दिसंबर, 2023 को कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद



केजरीवाल और एलजी सक्सेना के बीच शाह को डीडीसीडी के अध्यक्ष पद से हटाने पर आम सहमति के अभाव में मामला राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। अदालत को यह भी बताया गया कि उपराज्यपाल ने अनुच्छेद 239ए के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया है कि शाह को डीडीसीडी कार्यालय में तब तक प्रवेश की अनुमति नहीं दी

जाएगी जब तक राष्ट्रपति इस मुद्दे पर फैसला नहीं लेते। एलजी ने जवाब में कहा था कि जब तक राष्ट्रपति इस मामले पर फैसला नहीं सुनाते, तब तक पार्टियों के लिए आगे कोई कार्रवाई नहीं करना समझदारी होगी। 28 नवंबर, 2022 को शाह द्वारा सक्सेना के कार्यों को चुनौती देने के बाद उच्च न्यायालय ने एलजी से जवाब मांगा था।

2012-13 में 37 हजार करोड़ रुपये था। गुप्ता ने कहा कि सरकार के इन प्रयासों का लाभ गांव, गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं सहित सभी वर्गों को मिल रहा है। चर्चा में हिस्सा लेते हुए शिवसेना के श्रीरंग अम्पा बर्ण ने कहा कि यह समावेशी बजट है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार ने लक्षित लाभों के सार्वभौमिकरण के साथ ही कई योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू की हैं। उन्होंने कहा कि यह बजट मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल का सबसे अच्छा बजट है जिसमें सभी वर्गों पर ध्यान दिया गया है। जदयू के महाबली सिंह ने कहा कि हर साल सरकारें बजट पेश करती हैं, लेकिन आजादी के बाद से आज तक देश के करोड़ों लोगों की तरवीर नहीं बदली है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता को केंद्र सरकार से इस बजट में राज्य को विशेष दर्जा दिये जाने की पुरानी मांग पूरी होने की उम्मीद थी। सिंह ने कहा कि देश में जातीय जनगणना कराई जानी चाहिए और जातियों की आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी तय की जानी चाहिए।

दक्षिण अफ्रीका से 16 चीते और लाये जाएंगे

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि आगामी महीनों में 14 से 16 चीतों को भारत लाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार वन्यजीव संरक्षण और संवहनीयता के लिए समग्र प्रयास कर रही है। भावी पीढ़ियों के लिए प्रकृति को बचाने की जरूरत पर जोर देते हुए मंत्री ने यह भी कहा कि किसी वस्तु का इस्तेमाल करने के बाद उसे कचरे के रूप में फेंकने वाले मॉडल के लिए अब कई जगह नहीं हैं। सिंधिया ने कहा कि वन्यजीव संरक्षण और उनका विकास सुनिश्चित करना हमारी परंपरा और हमारी निधि 1 का एक अहम हिस्सा है ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए उसे अक्षुण्ण बनाए रख सकें और उसे आगे बढ़ा सकें। बीते करीब नौ साल में सरकार की वन्यजीव संरक्षण पहलों के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए सिंधिया ने कहा कि आने वाले महीनों में 14 से 16 और चीते भारत लाए जा सकते हैं। फिलहाल, सरकार चीता परियोजना के दूसरे चरण पर काम कर रही है और उसने दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता किया है। चीतों को दक्षिण अफ्रीका से लाया जाएगा। चीता परियोजना के तहत, आठ चीतों को नामीबिया से हवाई मार्ग से भारत लाया गया था।

भारतीय सीमा में फिर पाक ड्रोन की घुसपैठ तालाशी अभियान जारी

नई दिल्ली। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने एक बार फिर ड्रोन के जरिए ड्रग्स और हथियार भेजने की पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर दिया। पंजाब की अंतरराष्ट्रीय सीमा के अंदर घुसे एक पाकिस्तानी ड्रोन को जवानों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी कर खदेड़ दिया। बीएसएफ की तरफ से ये जानकारी दी गई है। बीएसएफ ने बताया कि बुधवार रात करीब 9.40 बजे पंजाब के गुरदासपुर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे एक पाकिस्तानी ड्रोन को गोलीबारी कर खदेड़ा दिया गया। जानकारी के मुताबिक गश्त के दौरान गुरदासपुर सेक्टर के अरिया बीओपी पर बीएसएफ के जवानों को एक पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करते दिखा। इसके बाद जवानों ने ड्रोन पर तकरीबन 16 राउंड गोलीबारी की और रोशनी करने वाले बम भी चलाए। कुछ देर में ही ड्रोन गोलीबारी के चलते फ्लैगिंग के ऊपर से ही पाकिस्तान की तरफ वापस चला गया। घटना के बाद वरिष्ठ अि कारिर्यों को इसकी सूचना दी गई और इलाके में इस वक्त भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

नीरव मोदी के बहनोई की हांगकांग यात्रा पर 4 हफ्ते में फैसला करेगा बंबई हाईकोर्ट, एससी ने दिया निर्देश

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के बहनोई मैक मेहता को हांगकांग जाने की अनुमति दिए जाने के खिलाफ दायर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका बंबई उच्च न्यायालय को बरहस्पतिवार को वापस भेज दी। न्यायालय ने इस मामले में अदालत से चार सप्ताह में नए सिरे से फैसला सुनाने को कहा। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में आरोपी है। सीबीआई का आरोप है कि मेहता ने पीएनबी धोखाधड़ी मामले में बड़ी मात्रा में हेराफेरी की राशि को अपने व अपनी पत्नी के बैंक खाते में भेज दिया था। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा एवं न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की पीठ ने कहा कि सीबीआई और मेहता दो सप्ताह की अवधि के भीतर उच्च न्यायालय में अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल कर सकते हैं और उसके बाद दो सप्ताह के भीतर याचिका पर फैसला किया जाएगा। न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि मेहता की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने सीबीआई को मेहता के दो विदेशी बैंक खातों के विवरण हासिल करने और



उनकी जांच करने के लिए “अधिकार पत्र” देने पर सहमति व्यक्त की है। सीबीआई ने अपने निदेशक, बैंकिंग सुरक्षा धोखाधड़ी शाखा, मुंबई के मार्फत बंबई उच्च न्यायालय के 23 अगस्त 2022 के आदेश को शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने मेहता को हांगकांग की यात्रा करने और वहां तीन महीने रहने की अनुमति दी थी। उच्च न्यायालय ने मुंबई के

विशेष सीबीआई न्यायाधीश का आदेश बरकरार रखा था और सीबीआई द्वारा मेहता के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर खारिज कर दिया था और उसे हांगकांग जाने की अनुमति दी थी। मेहता ब्रितानी नागरिक है और वह अपने परिवार के साथ हांगकांग में रहता है। वह मुंबई की अदालत के समक्ष पेश होने के लिए आठ सितंबर, 2021 को भारत आया था।

जितना कीचड़ उछालोगे, कमल उतना ही खिलेगा : प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अडाणी समूह से जुड़े मामलों पर विपक्षी दलों के आरोपों के बीच बरहस्पतिवार को कहा कि उनके ऊपर जितना कीचड़ उछाला जाएगा, कमल उतना ही खिलेगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही। ‘कमल केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का चुनाव चिह्न है। प्रधानमंत्री ने जैसे ही जवाब देना आरंभ किया वैसे ही कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्य आसन के निकट आ गए और नारेबाजी करने लगे। सदस्यों की नारेबाजी के बीच मोदी ने कहा, ‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने महत्वपूर्ण सदन में कुछ लोगों का व्यवहार, कुछ लोगों की वाणी ना सिर्फ सदन को बल्कि देश को निराश करने वाली रही है। उन्होंने कहा, ‘इस प्रकार की प्रवृत्ति के सदस्यों को मैं यही कहूंगा ‘कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाब।



जो भी जिसके पास था, उसने दिया उछाल। अच्छा ही है। जितना कीचड़ उछालोगे, कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। मोदी ने विक्षी दलों पर तंज कसते हुए कहा कि इसलिए कमल ना सिर्फ सदन को बल्कि देश को निराश करने वाली रही है। उन्होंने कहा, ‘इस प्रकार की प्रवृत्ति के प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे का उल्लेख करते हुए कहा कि

उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा कि कांग्रेस ने साठ सालों में देश में मजबूत बुनियाद रखी और मोदी उसका श्रेय ले रहे हैं। मोदी ने कहा कि जब 2014 में वह देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्हें नजर आया कि 60 साल में कांग्रेस के परिवारश ने गड़बे ही गड़बे कर दिए हैं। उन्होंने कहा, ‘हो सकता है कि उनका इरादा नेक होगा, लेकिन उन्होंने गड़बे ही गड़बे कर दिए हैं। जब वह गड़बे

खोद रहे थे छह-छह दशक बर्बाद कर दिए थे उस समय दुनिया के छोटे-छोटे देश भी सफलता के शिखरों को छू रहे थेकू आगे बढ़ रहे थे। प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान विपक्षी सदस्य अडाणी समूह से जुड़े मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित किए जाने की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे।

कांग्रेस सांसद का लोकसभा में नोटिस, पीएम की अदानी के साथ विदेश यात्राओं की मांगी जानकारी

नई दिल्ली। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब देने के एक दिन बाद कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने गुरुवार को लोकसभा में स्थगन नोटिस देकर अदानी के साथ प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं का ब्योरा मांगा। नोटिस में कहा गया है, उद्योगपति गौतम अदानी के साथ प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा और विदेशी टैंडर्स में ग्रुप को मिलने वाले लाभ पर चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने बुधवार को भारत को कमजोर बनाने पर विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि देश ताकतवर हो गया है और दूसरे देशों पर दबाव बना रहा है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी चर्चा की मांग करते हुए चीन-वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएससी) मुद्दे पर स्थगन नोटिस दिया। नोटिस में उन्होंने कहा, अप्रैल 2020 से चीन लगातार जमीन हड़पने में लगा हुआ है। 16 जनवरी 2023 तक भारत और चीन के बीच कर्मांडर स्तर की 17 दौर की वार्ता हो चुकी है, जिसमें बहुत कम सफलता मिली है। इस दौरान चीन अपने सैनिकों के लिए पुलों, सड़कों और आवास सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण करना जारी रखे हुए है। चीन एकतरफा तरीके से यथास्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर में झड़पें चीन की स्थिर आक्रामकता का एक और संकेत हैं। इस तरह की आक्रामकता एक क्षेत्रीय दायरे तक सीमित नहीं है, जैसा कि संघर्ष स्थल से लगभग 2000 किलोमीटर दूर अरुणाचल प्रदेश में हुई झड़पों से जाहिर होता है।



अडाणी मामले: हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच संबंधी याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट उद्योगपति गौतम अडाणी के नेतृत्व वाले कारोबारी समूह पर ‘हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट’ की जांच के लिए शीर्ष अदालत के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में समिति का गठन करने के वास्ते केंद्र को निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। अधिवक्ता विशाल तिवारी ने प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की एक पीठ से मामले को तुरंत सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। उन्होंने पीठ से अनुरोध किया कि उनकी याचिका पर मामले में दर्ज अन्य याचिकाओं के साथ शुक्रवार को सुनवाई की जाए। अधिवक्ता तिवारी द्वारा दायर जनहित याचिका में बड़े कारोबारी घरानों को दिए गए 500 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण के लिए मंजूरी नीति की निगरानी को लेकर एक विशेष समिति गठित करने के बारे में भी निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। शीर्ष अदालत में पिछले हफ्ते वकील एम. एल. शर्मा ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें अमेरिका की वित्तीय शोध कंपनी ‘हिंडनबर्ग रिसर्च’ के नाथन एंडरसन और भारत तथा अमेरिका में उनके सहयोगियों के खिलाफ कथित रूप से निर्दोष निवेशकों का शोषण करने और अडाणी समूह के शेयर के मूल्य को ‘कृत्रिम तरीके से गिराने के लिए मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। ‘हिंडनबर्ग रिसर्च’ द्वारा अडाणी समूह पर फर्जी लेनदेन और शेयर की कीमतों में हेरफेर सहित कई गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद समूह की कंपनियों के शेयर की कीमतों में भारी गिरावट आई है। अडाणी समूह ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह सभी कानूनों और सूचना सार्वजनिक करने संबंधी नीतियों को पालन करता है।

पटना। बिहार में भाजपा के आईटी सेल के राज्य संयोजक मनन कृष्णा ने गुरुवार को पटना में कहा कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत 37,76,05,305 लोगों को ऋण दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, जद(यु) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बयान के जवाब में मनन कृष्णा ने यह बयान दिया है। ललन सिंह ने युवाओं के लिए 2 करोड़ रोजगार सृजित करने के वादे को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा था। मनन कृष्णा ने कहा कि ललन सिंह का कहना है पिछले 9 सालों में 18 करोड़ नौकरियां हुईं, में उन्हें बताना चाहता हूं कि पीएमएमवाई योजना के तहत 37 करोड़ से ज्यादा लोग लाभान्वित हुए हैं और उनका कारोबार फल-फूल रहा है। वे न केवल अपने लिए कमाने में लगे हैं बल्कि दूसरों को रोजगार भी दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने लगातार कहा है कि वह 2 करोड़ नौकरियां पैदा करेगी, और केवल मुद्रा योजना के तहत दोगुने से अधिक दिया



है। कृष्णा ने कहा, केंद्र सरकार ने 79,648 स्टार्टअप को भी मान्यता दी है, जिनमें लाखों युवाओं को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने आगे कहा, आत्मनिर्भर भारत के तहत कर्ज लेकर कुल 46 लाख लोगों ने अपना कारोबार शुरू किया किया है। इसके अलावा देश में 5.31 लाख कॉमन सर्विस सेंटर से जुड़े। कृष्णा ने कहा, ललन सिंह की श्रेणी में आते हैं। केंद्र ने इस साल 10 लाख नौकरियां देना भी शुरू कर

दिया है। रोजगार भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में औसतन 15 लाख नए खाते (यूएन) खोले गए। पिछले साल अक्टूबर में 12.94 लाख, सितंबर में 15.42 लाख, अगस्त में 16.94 लाख, जुलाई में 18.23 लाख, जून में 18.36 लाख, मई में 16.82 और पिछले साल अप्रैल में 17.08 लाख लोग ईपीएफओ से जुड़े। कृष्णा ने कहा, ललन सिंह ने देश के प्रत्येक व्यक्ति को 15 लाख रुपये पर एक सवाल भी पूछा, मैं ललन

सिंह को चुनौती देना चाहता हूं कि वह पीएम मोदी के 15 लाख रुपये के बयान को मीडिया में जारी करें या उनके खिलाफ टिप्पणी करने के लिए माफी मांगें। रिपोर्ट के अनुसार, लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सिंह ने पीएम मोदी पर दो करोड़ नौकरियों और हर व्यक्ति के व्यक्तिगत खाते में 15 लाख रुपये की नकदी पर प्रतिक्रिया देने का आरोप लगाया था।

सम्पादकीय

कांग्रेस और भाजपा के लक्ष्य का फर्क

वैसे तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कई मामलों में बड़ा फर्क है लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो लक्ष्य तय करने के मामले में दोनों में जमीन आसमान का अंतर दिखता है। कांग्रेस कभी भी बहुत बड़ा या महत्वाकांक्षी लक्ष्य नहीं तय करती है, जबकि भाजपा हमेशा बड़ा लक्ष्य तय करती है। कई बार उसे हासिल भी कर लेती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लक्ष्य हासिल नहीं हुआ तो उससे हतोत्साहित होकर पार्टी ने अगली बार लक्ष्य छोटा कर दिया। अगली बार उससे भी बड़ा लक्ष्य रखा जाता है। मिसाल के तौर पर भाजपा ने अगले लोकसभा चुनाव में चार सौ सीट जीतने का लक्ष्य रखा है, जबकि कांग्रेस का लक्ष्य अपनी सीटों को दोगुना करने भर का है [भाजपा ने मिशन चार सौ के लिए काम भी शुरू कर दिया है। अपनी जीती हुई 303 लोकसभा सीटों के अलावा पार्टी ने 160 और सीटों की पहचान की है, जहां वह पिछली बार दूसरे या तीसरे नंबर पर रही थी या उस समय की उसकी सहयोगी पार्टी ने वह सीट जीती थी। इन 160 सीटों पर पार्टी ने केंद्रीय मंत्रियों की जिम्मेदारी लगाई है। हर मंत्री के जिम्मे तीन या चार सीटें हैं। इसके अलावा इन सीटों पर राज्यसभा के सांसदों को खासतौर से जिम्मा दिया गया है। साथ ही पार्टी ने एक लाख कमजोर बूथ की पहचान की है, जहां अलग से काम हो रहा है। बूथ मजबूत करने के लिए पन्ना प्रमुख बढ़ाए जा रहे हैं। अब मतदाता सूची के हर पन्ने के लिए दो प्रमुख नियुक्त करने की चर्चा है।ध्यान रहे भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव में 273 सीट जीतने का लक्ष्य रखा था। उस समय तक भाजपा को पहले कभी पूर्ण बहुमत नहीं हासिल हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 1998 और 1999 में पार्टी को अधिकतम 183 सीटें मिली थीं। इसलिए 273 का लक्ष्य बहुत बड़ा था, जिसे पार्टी ने हासिल कर लिया। उसे 2014 में 284 सीटें मिलीं। इसके बाद 2019 के चुनाव में लक्ष्य बढ़ा कर तीन सौ सीट का कर दिया गया। सारी पार्टियां और राजनीतिक जानकार इसका मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि इस बार भाजपा की सीटें घटेंगी पर उसने 303 सीटें जीत लीं। इस बार उसने चार सौ सीटों का लक्ष्य रखा है और उसे हासिल करने का प्रयास शुरू कर दिया है।

दूसरी ओर कांग्रेस व अन्य प्रादेशिक पार्टियों का लक्ष्य बहुत छोटा है। कांग्रेस का लक्ष्य अपनी मौजूदा सीटों की संख्या को दोगुन करने का है। अभी उसके पास 52 सीटें हैं और पार्टी के नेताओं का मानना है कि वे बहुत खुश हो जाएंगे, अगर सीटों की संख्या एक सौ पार कर जाए। यानी तीन अंक में पहुंच जाए। इसी को ध्यान में रख कर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हुई है। कांग्रेस की यात्रा जिन 14 राज्यों से गुजरी है उन राज्यों में भाजपा को अपनी सीटें बचानी हैं या बढ़ानी हैं। उसकी मिली ज्यादातर सीटें उन्हीं राज्यों में हैं। अन्य विपक्षी पार्टियों का लक्ष्य तो और भी छोटा है। वे अपने जीतने की बजाय इस प्रयास में लगे हैं कि भाजपा की 50–60 सीटें कम कर देनी हैं ताकि उसको बहुमत न मिले।

डंडे से समाज सुधार

सरमा को खुद से पूछना चाहिए कि मध्य और समृद्ध वर्ग के परिवारों में बाल विवाह क्यों नहीं होते? जिन समस्याओं का संबंध सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि से है, उनका हल डंडे के जोर से ढूंढना एक अतार्किक नजरिया है। हर भावनात्मक और सामाजिक मामले को सियासी हथियार बनाने का भारतीय जनता पार्टी का उत्साह इतना ज्यादा है कि इसके फौरी और दीर्घकालिक दुष्परिणामों की वह तनिक भी फिक्र नहीं करती है। उसका यह उत्साह फिलहाल असम में देखने को मिल रहा है, जहां के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा उग्रता की होड़ में आगे निकलने का कोई मौका नहीं चूकते। अब उन्होंने बाल विवाह रोकने के नाम पर असम एक बड़ी सामाजिक समस्या खड़ी कर दी है। सैकड़ों कमउम्र लड़कियों का इस वजह से भविष्य खतरे में पड़ गया है, क्योंकि उनके नव–विवाहित पतियों को जेल भेज दिया गया है। इस तरह जो लोग अज्ञान, गरीबी और पारंपरिक पिछड़ेपन के शिकार हैं, उन्हें ही इसकी सजा भुगतने को भी कहा जा रहा है। क्या यह प्रश्न इस मौके पर नहीं उठाना जाना चाहिए कि अगर सरकारों ने संवैधानिक वायदे के मुताबिक सबकी शिक्षा और सबके जीवन स्तर में सुधार को सुनिश्चित किया होता, तो आज लाखों कमउम्र लड़के–लड़कियां उस सपने से वंचित नहीं होते, जिसकी वजह से वे छोटी उम्र में विवाह का बोझ उठाने को तैयार हो जाते हैं? सरमा को खुद से पूछना चाहिए कि मध्य और समृद्ध वर्ग के परिवारों में बाल विवाह क्यों नहीं होते? जिन समस्याओं का संबंध सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि से है, उनका हल डंडे के जोर से ढूंढना एक अतार्किक नजरिया है। गौरतलब है कि असम सरकार ने राज्य में होने वाले बाल विवाह, प्रसव के दौरान माताओं और नवजात शिशुओं की ऊंची मृत्यु दर पर अंकुश लगाने के लिए६ अभियान चलाया है। इसके तहत 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों के खिलाफ पोक्सो अि नियम और 14 से 18 साल तक की उम्र वाली लड़कियों से शादी करने वालों के खिलाफ बाल विवाह रोध्थाम अधिनियम– 2006 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि असम सरकार राज्य में बाल विवाह की सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए कृतसंकल्प है।

विनोबा भावे : बापू के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी

वे समर्पण की नजीर थे। पूर्णतः एकनिष्ठ। किसी भी तरह के संशय से परे। अविचल और अडिग। चरैवैते कि मंत्र को उन्होंने जीवन में उतार लिया था। उन्होंने अपने पांवों से इस महादेश को ओरछोर नापा। माषाए उनके चेरी थीं। कंठ में सरस्वती। प्रसिद्धि की चाह नहीं। आवश्यकताएं कम से कमतर। गीता पर अर्पूर् और अनूठा अधिकार। अनुवाद में अद्भुत गति। संगीत से अनुराग। अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए दान की याचना। अहिंसाप्रती और जयाजगत के मंत्र–दाता...

यह थे विनोबा। संत विनोबा भावे। जन्मना विनायक नरहरि। आत्मा से सर्वोदयी। भूदान–यज्ञ के प्रणेता। राष्ट्र के शिक्षक। महात्मा गांधी के आध्यात्मिक या उत्तराधिकारी पुत्र। भारत छोड़ो आंदोलन के पहले सिपाही। श्रीमद्भगवद्गीता के मर्मज्ञ और प्रवचनकार। साबरमती के संत के अनन्य अनुयायी। वह समस्त भारतीय भाषाओं के लिए उरी तरीह एह लिपि के अनुयायी थे, जैसे तमाम योरोपीय भाषाओं के लिए एक रोमन लिपि। देवनागरी को वह समस्त भारतीय भाषाओं के लिए उपयुक्त मानते थे। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। प्रेम की अमोघ शक्ति और सत्ता में उनकी गहरी आस्था थी। वह कदा करते थे–मुझे प्रेम छोड़ कोई कनकीक नहीं पड़ा, क्योंकि शक्ति में मेरा कोई विश्वास नहीं।22 लोक ने उन्हें ससम्मान आचार्य कहकर पुकारा। कृतज्ञ राष्ट्र ने सन् 1983 में उन्हें भारतरत्न से सम्मानित किया। इससे पच्चीस साल पहली ही उन्हें प्रतिष्ठित रमन मैग्सेसे अवार्ड से

सम्पादकीय/लेख

समान नागरिक संहिता : भारतीय परिवेश में है जरूरी



भारत में हिंदू स्त्रियों की स्थिति 200 वर्ष पहले दयनीय थी। पंडिता रमाबाई ने कहा था भारत तब तक तरक्की नहीं कर सकता और संसार के देशों में कोई स्थान नहीं बना सकता जब तक कि हिंदू घरों में हिंदू स्त्रियां जो मां भी हैं, की स्थितियां नहीं सुधरती। बत्त्वियों को बालपन में शादी कर उपेक्षा के अंधकार में ढकेल दिया जाता है। इसके साथ ही अपने मातृ कर्तव्यों के बारे में अनजान, खासकर सामान्य पोषण संबंधी नियमों से अनजान और ज्यादा निम्नस्तर को प्राप्त होती हैं। यह याद रखना होगा कि वह भी एक लड़की है तथा बच्चे को जन्म देकर मां बनती है। 14–15 की उम्र में उससे यह

आशा नहीं की जा सकती कि वह अपने बच्चों का सही ढंग से पालन कर सकेगी। हम देख रहे हैं कि हिंदू नरें कर सकता और संसार के देशों ार हुआ है। सती प्रथा, बाल विवाह का विरोध हुआ है। कानून में भी मां भी हैं, की स्थितियां नहीं सुधरती। आवश्यक बदलाव कर लड़कियों को जकड़नों, बंधनों से मुक्त किया गया है। आज उनके विवाह की उम्र क्रमशरू बढ़ाकर 18–21 वर्ष की गई है, मुफ्त शिक्षा का उपहार दिया गया है।

हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में बदलाव लाया गया और लड़कियों की उम्र बढ़ाकर 18 वर्ष लड़कों के विवाह उम्र 21 वर्ष की जमा दिया गया है।

हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में बदलाव लाया गया और लड़कियों की उम्र बढ़ाकर 18 वर्ष लड़कों के विवाह उम्र 21 वर्ष की जन्म देकर मां बनती है।

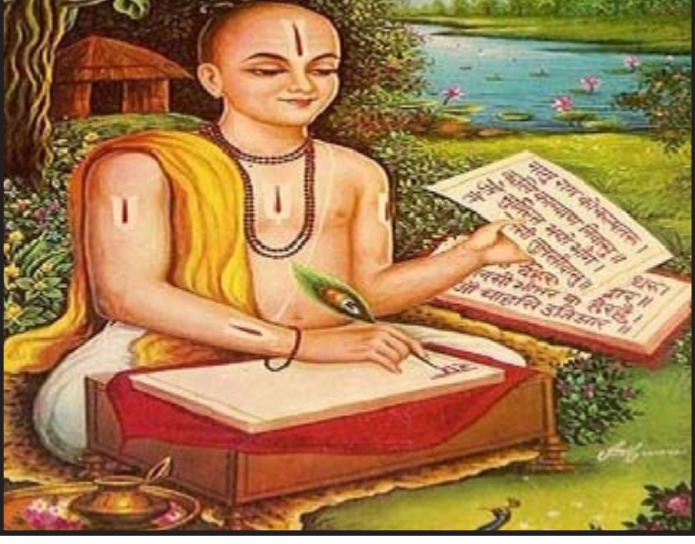
14–15 की उम्र में उससे यह

आशा नहीं की जा सकती कि वह अपने बच्चों का सही ढंग से पालन कर सकेगी। हम देख रहे हैं कि हिंदू नरें कर सकता और संसार के देशों ार हुआ है। सती प्रथा, बाल विवाह का विरोध हुआ है। कानून में भी मां भी हैं, की स्थितियां नहीं सुधरती। आवश्यक बदलाव कर लड़कियों को जकड़नों, बंधनों से मुक्त किया गया है। आज उनके विवाह की उम्र क्रमशरू बढ़ाकर 18–21 वर्ष की गई है, मुफ्त शिक्षा का उपहार दिया गया है।

हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में बदलाव लाया गया और लड़कियों की उम्र बढ़ाकर 18 वर्ष लड़कों के विवाह उम्र 21 वर्ष की जन्म देकर मां बनती है।

14–15 की उम्र में उससे यह

तुलसी रामायण पर विवाद



राष्ट्रीय एकता को ही गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। रामचरितमानस हिन्दू धर्म के अनुयायियों का सर्वोच्च आस्था ग्रंथ है। करोड़ों लोग इस ग्रंथ का हर दिन स्वाध्याय करते हैं। मौर्य ने इस ग्रंथ को लेकर सरकार से अनुर कृति का अनादर एवं बेवजह का विवाद खड़ा करना समझ से परे है। आखिर बहुसंख्य हिन्दू समाज कब तक सहिष्णु बन ऐसे हमलों को सहता रहेगा? कब तक रश्चर्वधर्म समभावश के नाम पर बहुसंख्य समाज ऐसे अपमान के घूँट पीता रहेगा? राजनीतिक दलों में एक वर्ग–विशेष के प्रति बढ़ते ेर्गार्मिक उन्माद पर तुरन्त नियन्त्रण किये जाने की जरूरत है क्योंकि अभी यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो उसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं जिनसे

वह, किस हास्यास्पद स्थिति तक पहुंच सकती है। भले ही यह विवाद बिहार के शिक्षा मंत्री और आरजेडी नेता चंद्रशेखर के इस बयान से शुरू हुआ कि रामचरितमानस के कुछ वोहे समाज के कुछ खास तबकों के खिलाफ हैं। देखा जाए तो रामचरितमानस के कई द्रोहों पर बहस बहुत पहले से चली आ रही है। सन् 1925 में बापू ने उन्हें विरोध ी बताया जाता है तो कुछ को स्त्री विरोधी । इसके पक्ष–विपक्ष में बहस विवेक के धागे से बंधी न रहे तो

है, क्या तलाक के बाद मुआवजा या भरण–पोषण का अधिकार चाहिए आदि। करीब–करीब सभी ने यही कहा– हां पसंद है पर मजहब की पाबंदियों के कारण कुछ कह नहीं सकती। आज इन बहनों को भी इन जकड़नों से निकलते की जरूरत है। शादी की उम्र अभी महज 15 वर्ष है। इतनी सी उम्र में शिक्षा मुश्किल से 10 क्लास हो सकती है और नौकरी कर अपने पांवों पर खड़े होने का सवाल ही नहीं उठता। यहां विवाह एक कंट्रैक्ट की तरह है जिसे कभी भी तोड़ा जा सकता है। पर यहां भी पुरुष को अधिक अधिकार दिए गए हैं।

मुहब्बन कानून की धारा 251 (2) के अनुसार पालकों और नाबालियों (लड़का–लड़की) का विवाह उनके अभिभावक द्वारा 15 वर्ष से कम में भी हो सकता है। इसी कानून के अनुसार एक मुस्लिम लड़के का विवाह तोड़ा जा सकता है यदि उसकी सहमति विवाह पर नहीं है। इसके अलावा तलाक के नियम भी पुरुषों के अलग और स्त्रियों के अलग हैं। उन्हें तलाक के बाद मासिक भत्ता देने का रिवाज नहीं है। यह सिर्फ इत भर है यानी तलाक से से तीन महीनों तक। इसके अलावा स्त्री एक शादी कर सकती है जो कि ठीक है। पर पुरुष एक ही समय में 4 विवाह कर सकता है और एक ही घर में रख सकता है और यदि वह पांचवां विवाह भी कर लेता है तो यह गैर कानूनी या गैर धार्मिक नहीं है, बस अनियमित है। ऐसी व्यवस्था में हर एक स्त्री को पति पर आधिकार नहीं होता जो उसे खुशी प्रदान कर सके। इसके अलावा शिया कानून में दो तरह

के विवाह होते हैं– परमानेंट और मुता विवाह यानि अस्थाई। एक शिया मुस्लिम, किसी भी धर्म की स्त्री यथा मुस्लिम, ईसाई, यहूदी या पारसी के साथ अस्थाई विवाह कर सकता है, पर किसी और धर्म वाली के साथ नहीं। पर एक शिया स्त्री किसी गैर मुस्लिम के साथ मुता निकाह नहीं कर सकती। इसमें शारीरिक संबंध एक तय अवधि के लिए बनाया जा सकता है। यह अवधि एक दिन, एक महीना, एक वर्ष या डायर यानी मुआवजा देना जरूरी है। इसमें यौन संबंध की अवधि ा तथा श्वावस्च दोनों ही तय होने चाहिए। स्त्री पुरुष में यह भेदभाव स्त्रियों की खुशी उन्नति, शारीरिक सुरक्षा, समाज, देश में उसकी भागीदारी को आहत करती है। इसी प्रकार भारत में हर धर्म, संप्रदाय में यथा ईसाई, पारसी, हिंदू, आदिवासी सभी में स्त्रियों के अधि कार की दृष्टि से एक ही नागरिक संहिता होनी चाहिए। देश की आधी जनसंख्या यदि संविधान में प्रदत्त

आज का राशिफल

मेघ :- योजनाओं के फलीभूत होने से मन प्रसन्न होगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मन दुविधायुस्त होगा। बिरोधियों प्रबलता से कार्य क्षेत्र में कठिनाईयों संभव। जीविका क्षेत्र में नए आयाम उत्साहित करेंगे।

बृश्म :- रोजगार के क्षेत्र में नए अवसर उत्साह का संचार करेंगे, परन्तु आवेश में लिया गया निर्णय हानिकारक हो सकता है। जो बीत गयी उसे भूल वर्तमान में जीने की चेष्टा करें।

मिथुन :- दूसरों की सफलता से अपने अन्दर हीन भावना ना पाले। नौकरी का वातावरण थोड़ा अरुचिकर और स्थान परिवर्तन के भी योग हैं। आवेश में लिया गया निर्णय से पश्चाताप संभव।

कर्क :- प्रयासरत कोई महत्वपूर्ण कार्य हल होने से मन प्रसन्न होगा। कार्य क्षेत्र में अपनी क्षमताओं का भरपूर लाभ उठाने का समय आ गया है। रोजगार में समस्याओं से हतोत्साहित ना हो।

सिंह:- नाजुक सम्बन्धों में भावनात्मक ताल–मेल बिठाने का प्रयत्न करें। नये कार्यां के क्रियान्वयन के लिए प्रयत्न तीव्र। कुछ नये उत्साह व कार्य क्षमता की अनुभूति करेंगे।

कन्या :- पुरानी घटनाओं के स्मरण से मन को कष्ट संभव। दूसरों की आलोचना का अपने मनोबल पर असर ना पड़ने दें। ग्रहों की अनुकूलता प्रगति के अच्छे अवसर प्रदान करेगी।

महंगे दूध की कसक

हाल के दिनों में दूध के दामों में लगातार वश्हि आम लोगों की परेशानी बढ़ाने वाली है। मूल रूप से शाकाहारी भारतीयों के खाने–पीने में दूध की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। छोटे बच्चे से लेकर वश्हड़ों तक के लिये दूध अपरिहार्य आहार ही है। स्वस्थ से लेकर बीमार तक , लोगों का जीवन बिना दूध के अधूरा है। ऐसे में दूध की कीमतों में वश्हि आम लोगों का बजट बिगाड़ देती है। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि दूध के कारोबार में बड़ी व सहकारी कंपनियों की खासी दखल रही है। अब इस क्षेत्र की बड़ी कंपनियां कीमतों की नियामक बन गई हैं। ऐसी स्थिति में कई भारतीयों के लिये दूध खरीदना टेढ़ी खीर बनती जा रही है। अधिकांश दिल्ली में दूध की सप्लाई करने वाली मदर डेरी ने गत दिसंबर में दूध के दाम में दो रुपये लीटर की वश्हि की थी, जिसे बीते साल में दामों में हुई पाँचवीं वश्हि बताया गया। इसके बाद अब दूसरी बड़ी सहकारी दूध कंपनी अमूल ने तीन रुपये प्रति लीटर दाम बढ़ा दिये हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पहले गुजरात की इस कंपनी ने नवंबर में भी दूध के दाम बढ़ाए थे। उपभोक्ताओं द्वारा सवाल अमूल की दोहरी कीमत नीति को लेकर भी उठाये जाते रहे हैं कि क्यों गुजरात व शेष देश में कीमतों में अंतर होता है? क्या इसके राजनीतिक निहितार्थ हैं? किसी उत्पाद की राष्ट्रीय स्वीकार्यता के आलोक में इसे देखा जाना चाहिए। वैसे तो देश भर में दू् 1 के दामों में वृद्धि के मूल में मांग व आपूर्ति का असंतुलन बताया जाता रहा है। गाय–भैंस के चारे के दामों में वृद्धि ने भी दूध उत्पादकों का मुनाफा कम किया है। जहां महंगाई की मार चारे पर पड़ी है, वहीं खेती के ट्रेंड में आये बदलाव से अब तक सहज उपलब्ध चारा मुश्किल से मिलता है। पहले जो पराली आदि पालतू जानवरों के लिये सहज उपलब्ध थी, उसे किसान अब खेतों में यूं ही जला देते हैं। वैसे जहां कंपनियां दूध के दामों में वृद्धि के पीछे लागत में वृद्धि बता रही हैं, वहीं मांग व आपूर्ति का असंतुलन भी दाम बढ़ने का बड़ा कारक है। खेती–पशुपालन के प्रति नई पीढ़ी का घटता रुझान और खेती योग्य जमीन के बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उद्देश्य, भवन निर्माण व अन्य कार्यों के लिये इस्तेमाल से कृषि भूमि का संकुचन हुआ है। जिसका असर पशुपालन पर भी हुआ है। बताते हैं कि आम भारतीयों के खाने पर होने वाले मासिक खर्च का बीस फीसदी दूध व उसके उत्पादों पर होता है। गाँवों के मुकाबले शहरों में दूध की उपलब्धता में कमी के चलते यह खर्च बढ़ जाता है। यूं तो पिछले दशक में समाज के हर वर्ग में दूध व उसके उत्पादों का उपयोग बढ़ा है,लेकिन उस अनुपात में आपूर्ति नहीं बढ़ी। पिछले दिनों कई राज्यों में लंपी रोग से लाखों गाँवों के मरने का भी दूध की आपूर्ति पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। वहीं भैंसों में मुंह–खुर रोग का असर देखा गया है। बहरहाल, उत्पादन में कमी के बावजूद बाजार में दूध, उससे बने उत्पादों तथा मिठाइयों में कोई कमी नजर नहीं आती। ऐसे में सवाल उठता है कि बाजार में दूध की बहार कैसे है? कैसे आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना हुआ है? क्या इसमें बड़ी भूमिका रासायनिक व मिलावटी दूध की है? वैसे भी जिस पैमाने पर दूध की जांच जिम्मेदार विभाग द्वारा की जानी चाहिए थी, वह नहीं हो रही है। निगरानी करने वाले तंत्र की पाँचों उंगलियां धी में रहती हैं और कृत्रिम दू् 1 आपूर्ति करने वालों की पौ–बारह। वहीं दुग्ध उत्पादक लगातार चारे की मुद्रास्फीति की बात कहते रहे हैं। वैसे सरकारों के स्तर पर दूध उत्पादन बढ़ाने और इस दिशा में शोध–अनुसंधान को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि दुनिया में सबसे बड़ी आबादी होने की ओर बढ़ रहे देश के लिये दूध की सामान्य आपूर्ति हो सकेगी? सरकार को यथाशीघ्र ऐसे कदम उठाने होंगे कि दुग्ध उत्पादकों को सही कीमत मिल सके और उपभोक्ता को गुणवत्ता का दूध।

कर करेत्तर राजस्व वसूली एवं राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न

प्रयाग दर्पण संवाददाता
मऊ। गुरुवार को जिलाधिकारी अरुण कुमार की अध्यक्षता में कर करेत्तर राजस्व वसूली एवं अन्य राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कर प्राप्तियों पर विभागवार समीक्षा की गई। इस दौरान व्यापार कर,स्टॉप शुल्क, आबकारी, विद्युत, परिवहन, खनन आदि में लक्ष्य के सापेक्ष कम प्राप्तियों पर जिलाधिकारी ने इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने तहसील वार आर.सी. वसूली की समीक्षा के दौरान लक्ष्य के सापेक्ष कम वसूली पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए समस्त तहसीलदारो को अगले 1 महीने में आर.सी. वसूली में सुधार लाने के निदेश दिए। अन्यथा के स्थिति में प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने की चेतावनी भी दी। उन्होंने अमीन वार आरसी वसूली की नियमित जांच करने के साथ ही सभी आरसी को ऑनलाइन करने के भी निर्देश समस्त उप जिलाधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को संबंधित तहसीलों में बिना एनओसी के संचालित ईंट भट्टों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा।जनपद स्तर पर 10 बड़े



बकायेदारों से वसूली की चर्चा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी तहसीलों में वसूली की स्थिति ठीक ना पाए जाने पर तहसीलदारों को इन में सुधार लाने को कहा। जन शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी शिकायतों को गुणवत्तापूर्ण ढंग में निस्तारित करने साथ ही संतोषजनक रिपोर्ट लगाने को कहा। इसके लिए उन्होंने समस्त उप जिला अधिकारियों (न्यायिक) को प्रतिदिन असंतोषजनक निस्तारण वाले शिकायतों के शिकायतकर्ता से बातचीत कर उससे

संक्षिप्त खबरे

ट्रक की चपेट में आने से मासूम की दर्दनाक मौत
घोसी, मऊ। घोसी कोतवाली क्षेत्र के अमिला-बोझी मार्ग पर नवकापुरा के निकट गुरुवार की सुबह लगभग ९:30 बजे बोझी की तरफ से आ रहे बाइक सवार को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी जिसमें बाइक पर बैठे 6 वर्षीय रक्षक बॉसफोर की दर्दनाक मौत हो गयी। बता दे कि घोसी कोतवाली क्षेत्र के गोफा निवासी प्रेमचंद बॉसफोर अपने रिश्तेदारी में बुधवार की शाम घोसी कोतवाली क्षेत्र के सोहड़ गाँव मे एक तिलक परिवार में सह परिवार गए थे गुरुवार की सुबह लगभग 9:30 बजे प्रेमचंद बॉसफोर के छोटे पुत्र गोविंद के साथ पोता रक्षक भी बाइक से अपने घर गोफा जा रहे थे कि पीछे से आ रही ट्रक सूपी 65 एलटी 4741 की चपेट में आने से रक्षक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गयी। सूचना पर पहुँचे अमिला चौकी प्रभारी शव को कब्जे में लेकर घोसी कोतवाली लाया तो वही कुछ ही देर पुलिस द्वारा ट्रक को भी कब्जे में लेकर घोसी कोतवाली लाया गया। मृतक रक्षक के दादा प्रेमचंद बॉसफोर की तहरीर पर घोसी कोतवाली पुलिस ने उक्त वाहन चालक के खिलाफ सम्बंधित धारा में मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही शुरू कर दी है।

एक पिकअप वाहन से तीन राशि मवेशी बरामद, तीन अभियुक्त गिरफ्तार
मऊ। गुरुवार को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान ठेकुलिया घाट वल के पास से एक पिकअप वाहन (सूपी 54 टी 4788) में कूरतपूर्वक लाद कर वल हेतु ले जायी जा रही तीन राशि मवेशी (भैस) तथा दो अदद लोहे का चापड़ बरामद कर अभियुक्तगण सुनील राजभर पुत्र अश्वेश राजभर निवासी कोल्हाण थाना दक्षिणटोला, मो0 दानिश पुत्र उर्वैलद रहमान, मो0 अल्लमस पुत्र परवेज अहमद निवासीगण पटानटोला थाना कोतवाली जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुकों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 43,23 धारा 11(1)डी पशुकूटारा अधिनियम व बरामद अवैध चाकूओं के सम्बन्ध में आयुद्ध अधिनियम का अभियोग पंजीकृ त कर चालान न्यायालय किया गया तथा बरामद पिकअप वाहन को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया।

लावड़ में गरजा प्रशासन का बुलडोजर, तालाब से हटाया अवैध कब्जा

मेरठ। मेरठ के लावड़ जमालपुर गांव में तालाब की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए कमरों पर प्रशासन का महाबली गरजा। कई बार नोटिस देने के बाद भी कब्जा नहीं हटाया गया।सरधना तहसील के नायाब तहसीलदार जतिन गोस्वामी ने बताया कि जमालपुर गांव में सरकारी तालाब पर कुछ कब्जाधारियों ने सालों से कब्जा किया हुआ था। सभी को तहसीलदार न्यायालय से बेदखली के आदेश थे।जुलाई 2022 में कब्जा मुक्त कराया था। जिसके, बाद फिर से कब्जा हुआ तो चेतावनी देकर कब्जा हटाने के लिए कह दिया गया था। लेकिन, कब्जाधारी नही माने। जिसके बाद लगभग तीन पक्के कमरा का निर्माण किया और पशु बांधे जाने लगे।गुरुवार को सरधना तहसील की टीम पुलिस बल के साथ गांव पहुंची। प्रशासन के बुल्डोजर ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करते हुए सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया। कब्जााारियों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस के सामने उनकी एक नहीं चली। चेतावनी दी कि यदि दोबारा कब्जा किया तो कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

मुख्यालय से सटे सात चेकडैम खुद प्यासे, योजना पर बहा रहे आंसू

चित्रकूट। करोड़ों रुपये की लागत से सिद्धपुर और कोलगढहिया गांव में बनें सात चेकडैम बेकार साबित हो रहे हैं। इन चेकडैमों को वर्षा जल संचय को बनाया गया था, लेकिन यह सभी सूखे पड़े हैं। जीव-जंतुओं की प्यास बुझाने वाले सातों चेकडैम खुद प्यास से बेहाल हैं और सरकारी योजनाओं पर आंसू बहा रहे हैं।गुरुवार को बुंदेली सेना जिलाध्यक्ष अजीत सिंह ने बताया कि मुख्यालय से सटे दोनों ग्राम पंचायतों में इन चेकडैमों के आसपास खुदाई और चेकडैमों की मरम्मत कराए जाने की सख्त जरूरत है। गर्मी के दिनों में पहाड़ किनारे बने यह चेकडैम जानवरों और पशु-पक्षियों के लिए बड़े सहारे सिद्ध होते थे। इन्हीं से जानवर अपनी प्यास बुझाते थे, लेकिन अब यह चेकडैम सूखे पड़े हैं। गर्मी अभी दूर है, लेकिन चेकडैम पानी संचय करने की क्षमता खो चुके हैं। सिद्धपुर गांव में तीन और कोलगढहिया में चार ऐसे चेकडैम हैं। जिनके आसपास बड़े एरिया में खुदाई, सफाई और मरम्मत की जरूरत है। चेकडैम निर्माण करने वाले विभाग को अब इनकी सुघ नहीं है। कम लागत में सात चेकडैम फिर से पानीदार हो सकते हैं। बुंदेली सेना ने जिलाधिकारी से मांग की है कि मुख्यालय से सटे ग्राम पंचायतों में पहाड़ किनारे नालों में बने इन चेकडैमों को पानीदार बनाया जाये।

बुर्जी में लगी आग से भूसा जलकर राख
मथुरा। बुधवार की रात्रि थाना मगोर्ग के गांव नगला अड्डा के पास अज्ञात व्यक्ति ने एक किसान की भूसे की बुर्जी में आग लगा दी। इससे बुर्जी में रखा कई मन भूसा जलकर राख हो गया। पीड़ित किसान ने थाना मगोर्ग में तहसीर दी। बुधवार की रात्रि करीब ढाई बजे किसान उदयवीर सिंह के खेत पर बनी भूसे की बुर्जी में अचानक आग लग गई। खेतों पर रखवारी कर रहे लोगों ने देखा तो उन्होंने आग बुझाने का प्रयास किया बमुश्किल आग पर काबू पाया गया। लेकिन तब तक बुर्जी में रखा भूस जलकर राख हो गया। इस बारे में किसान उदयवीर सिंह ने बताया कि थाना मगोर्ग में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आग लगाए जाने की तहरीर दी है।

पेड़ पर लटका मिला युवक का शव
मथुरा। समीपवर्ती ग्राम धौरेरा में गुरुवार की सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब गांव के ही कुछ लोगों ने जंगलों में एक व्यक्ति के शव को पेड़ से लटका दिखा। जिसका सूचना पुलिस कंट्रोल रूम पर दी गई।

जिलाधिकारियों को चेतावनी पत्र जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्धारित समय सीमा के अंदर ही जाति एवं आय प्रमाण पत्र जारी करने के भी निर्देश दिए। जाति प्रमाण पत्र जारी करने की समीक्षा के दौरान जिलाधिाकारी ने कहा कि पूर्व में जारी प्रमाण पत्रों के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों को अकारण अस्वीकृत न किया जाए। उन्होंने नए जाति प्रमाण पत्र जारी करने के पूर्व पूरी जांच करने के भी निर्देश दिए। स्वामित्व योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को सर्वे का कार्य ठीक ढंग से पूर्ण करने को कहा जिससे बोर्ड द्वारा पुनः जांच हेतु सर्वे रिपोर्ट वापस ना भेजी जाए। बैठक के दौरान ही कुछ लेखपाल एवं कानूनगो द्वारा गलत रिपोर्ट लगाने का मामला संज्ञान में आने पर जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को क्षेत्र में कार्यरत लेखपाल एवं कानूनगो द्वारा गलत रिपोर्ट लगाने पर कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही एफआईआर दर्ज कराने के भी निर्देश दिए।।बैठक में जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण खराब पाए जाने पर जिलाधिकारी ने शून्य स्थिति वाले तहसीलों के उप

मुक्त विश्वविद्यालय ने किया सर्वाधिक प्रवेश करने वाले केंद्र समन्वयकों का सम्मान

प्रयाग दर्पण संवाददाता

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज में गुरुवार को प्रवेश सत्र जुलाई 2022 में हुए सर्वाधिक प्रवेश के उपलक्ष्य में क्षेत्रीय केंद्र समन्वयकों, प्रवेश अनुभाग के कर्मचारियों एवं 1000 से अधिक छात्र संख्या वाले 25 अध्ययन केंद्रों के समन्वयकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह ने सत्र जनवरी 2023 का ऑनलाइन प्रवेश प्रारंभ करने की घोषणा की। कुलपति प्रोफेसर सिंह ने प्रवेश विवरणिका सत्र 2022–2023 का विमोचन किया। विश्वविद्यालय के लोकमान्य तिलक शास्त्रार्थ सभागार में आयोजित प्रशस्ति 2022 की अ्ध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय के रगत जयंती वर्ष पर सर्वाधिक संख्या में प्रवेश होना एक बहुत बड़ी उपलब्ि है। उन्होंने कहा कि सीमित साधनों में हमें प्रदेश के गांव गांव तक पहुंचना है। यह काम हमारे क्षेत्रीय समन्वयक एवं अध्ययन केंद्रों के समन्वयक बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रीय केंद्र समन्वयकों, अध

दहेज हत्या में महिला समेत तीन दबोचे

चित्रकूट। पुलिस अधीक्षक श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देश पर पहाड़ी थाना पुलिस ने दहेज हत्या के वांछित एक महिला समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।गुरुवार को पहाड़ी थानाध्यक्ष यक्ष राम सिंह की अगुवाई में दरोगा रविकान्त राय, दरोगा शिवशरण तिवारी, सिपाही अजय कुमार, जयप्रकाश व महिला सिपाही रेखा भारती ने थाना क्षेत्र के नांदी गांव जाकर दहेज हत्या में वांछित महेश सिंह पुत्र स्व विरजीवनलाल, ननकी देवी पत्नी महेश सिंह तथा जगदीश सिंह पुत्र महेश सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इसी क्रम में सरसुआ थाने के थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह की अगुवाई में दरोगा सत्यमपति त्रिपाठी ने त्रिनेन्द्र पुत्र फूलचन्द्र निवासी व्योहरा के कब्जे से बीस लीटर महुआ शराब बरामद कर आबकारी अधिनियम में चालान किया है।

शास्वत यौगिक खेती एवं प्राकृतिक खेती पर विस्तृत चर्चा

प्रयाग दर्पण संवाददाता

प्रयागराज। अखिल भारतीय सरदार पटेल सेवा संस्थान आलोपीबांग परिसर में गुरुवार को 09 दिवसीय विराट किसान मेला 2023 के द्वितीय दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मनोरमा दीदी द्वारा की गयी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में ब्रह्मा कुमारी रेनू दीदी, ब्रह्मा कुमार सतीश भाई, उप कृषि निदेशक, प्रयागराज, जिला कृषि अधिकारी, कृषि रक्षा अधिकारी, भूमि संरक्षण अधिकारी, डा0 अजय कुमार, कृषि वैज्ञानिक के0वी0के0 नैनी, डा0 मुकेश पी0एम0 कृषि वैज्ञानिक, कृषि विश्वविद्यालय नैनी उपस्थित रहे। उप कृषि निदेशक, प्रयागराज द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए शास्वत यौगिक एवं प्राकृतिक खेती के फायदे के बारे में विस्तृत चर्चा की गयी। प्राकृतिक खेती जो पहले हुआ करती थी उसमें जो पोषक तत्व, जीवांश कार्बन, लामदायक जीव, मिट्टी में होते थे, उससे जो अन्न का उत्पादन होता

पुलिस लाइन में तैनात दरोगा ने गोली मारकर की आत्महत्या, अधिका्रियों में मचा हड़कंप **मेरठ।** मेरठ पुलिस लाइन में तैनात एक दरोगा ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। बताया गया कि दरोगा ने खुद की पिस्टल से कनपटी पर गोली मारकर वारदात को अंजाम दिया है। दरोगा का शव कमरे में बेड पर पड़ा मिला है।सूचना मिलते ही पुलिस लाइन में हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। हालांकि दरोगा ने किस वजह से सुसाइड किया है इसकी असली वजह सामने नहीं आई है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं एसएसपी रोहित सिंह सजवाण का कहना है कि पारिवारिक कलह के चलते दरोगा ने खुदकुशी की है।पुलिस के मुताबिक सहारनपुर के कोतवाली नगर में तैनात दरोगा इंद्रजीत ने पारिवारिक क्लेश के चलते मेरठ पुलिस लाइन स्थित अपने सरकारी आवास पर गोली मारकर आत्महत्या की है। एसपी ट्रैफिक एसपी देहात, एसपी सिटी, सीओ सिविल लाइन मौके पर पहुंचे। दरोगा की पुत्री (1९) और पुत्र (14) साल का है। बेटी ग्रेजुएशन कर रही है। दरोगा इंद्रजीत सिंह परिवार के साथ मेरठ स्थित पुलिस लाइन में रहते थे।

मुक्त विश्वविद्यालय ने किया सर्वाधिक प्रवेश करने वाले केंद्र समन्वयकों का सम्मान



ययन केंद्र समन्वयकों एवं प्रवेश विभाग के कर्मचारियों को सम्मानित करके उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर कुलसचिव कर्नल विनय कुमार एवं परीक्षा नियंत्रक श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह ने केंद्र समन्वयकों के प्रयास की सराहना की। प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत प्रवेश प्रभारी डॉ ज्ञान प्रकाश

यादव ने किया। श्री परचिंद्र कुमार बलवं ने संचालन तथा डॉ मनोज कुमार वलवंत ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर सम्मानित होने वाले समन्वयकों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। समारोह के दौरान ही कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह ने ऑनलाइन प्रवेश का शुभारंभ किया।

जनपद के 51 बच्चों को दी गयी सुपर हीरो किट

प्रयागराज। एस०आर०एस० 2019 के अनुसार प्रदेश में 5 वर्ष तक के शिशुओं की मृत्यु दर 48 1000 जीवित जन्म है। जबकि देश की 34, 1000 जन्म है। एस०डी०जी० गोल के अनुसार वर्ष 2025 तक इसे 25 किया जाना है। बच्चों में मृत्युदर एवं सगणता कम करने हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत 3 से 5 वर्ष के बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए शासन द्वारा पहल की गई है, बच्चों को कुपोषण से मुक्त रखने के लिए आईएपी द्वारा 12 जनपदों को चयनित करते हुए बच्चों को सुपर हीरो किट, देने के निर्णय लिए गये। यह जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी दिनेश सिंह ने दी।

इसी क्रम में वृहस्पतिवार को विकास भवन मीटिंग हाल में बच्चों को सुपर हीरो किट इंडियन अकादमी ऑफ पीडियाट्रिक्स द्वारा वितरित की गई। जिसमें यूनिसेफ द्वारा सहयोग किया गया। इस मौके पर आईएपी से डॉ रितु गुप्ता, संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य डॉ वी के मिश्रा, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ आशु पाण्डेय, जिला कार्यक्रम अधिकारी दिनेश सिंह व यूनिसेफ के देव कान्त शर्मा द्वारा बच्चों को सुपर हीरो किट एवं फूड देकर पोषण स्वास्थ्य स्वच्छता सम्बन्धी जानकारी दी।संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य डॉ वी के मिश्रा ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य है, इन्हें स्वस्थ रखने की ना जिम्मेदारी हम सभी की है।

इनके पोषण का ध्यान रखने के लिए हर स्तर पर हमें देखना होगा बच्चों को पीष्टिक भोजन जिससे उनके मन और शरीर पूरी तरह से विकसित हो और वो स्वस्थ रहे।इस अवसर पर को-ऑर्डिनेटर यूनीसेफ, बाल विकास परियोजना अधिकारी ओम प्रकाश यादव , बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में कार्यरत समस्त मुख्य सेविका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, अन्य कर्मचारियों एवं लाभार्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।



था उसे खाने से व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं। आज के समय में रसायनों एवं कीटनाशकों के प्रयोग से मिट्टी की उदरा शक्ति कम होती जा रही है। आज का किसान जहाँ एक ओर खेती की लागत बढ़ने, उत्पादों का उचित मूल्य न मिलने प्राकृतिक प्रकोपों तथा परेशान होकर आत्म हत्या कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर अत्याधिक रसायनिक खादों तथा कीटनाशक जहर से तैयार होे, उससे जो अन्न का उत्पादन होता

स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। अनेक प्रकार की बीमारियों और रोग बढ़ते जा रहे हैं युवा पीढ़ी खेती करना नहीं चाहती। ग्रामीण युवा लक्ष्य विहीन जीवन से परेशान होकर नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, उसे अपना भविष्य अंधकारमय दिख रहा है। जिस खेती को उत्तम कार्य कहा जाता रहा है अब किसानों को बोझ लग रही है, लोग इसे मजदूरी का कार्य समझने लगे हैं विकास की धुरी कमजोर होने अनाज, फल एवं सब्जियां मनुष्य के

यह बजट देश की खुशहाली में मील का पत्थर साबित होगा: गणेश केसरवानी

प्रयाग दर्पण संवाददाता

प्रयागराज। भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज के द्वारा मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के मेहता प्रेक्षागृह में अमृत काल का प्रथम आम बजट को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें समाज के प्रबुद्ध जनों ने अपनी सहभागिता निभाई।इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भाजपा जिला अध्यक्ष महानगर गणेश केसरवानी इस अवसर पर सम्बोधित करते हुये कहा कि यह बजट देश की खुशहाली में मील का पत्थर साबित होगा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पहली बार अमृत काल शब्द का इस्तेमाल किया। 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया था, उस वक्त ही उन्होंने 25 सालों के लिये देश के लिये का नया रोड मैप जारी किया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 25 साल की यात्रा नये भारत का अमृत काल है, ये अमृत काल हमारे सफल्यों की पूर्ति करेगा और हमें अंकावती के 100 साल तक ले जायेगा। उन्होंने कहा कि भारत ने तेजी से प्रगति की है ऐसे में विकास की संतुप्ति होनी चाहिये और हर गांव में सड़कें होनी चाहिये, सभी परिवार के पास बैंक खाता हो और हर पात्रता वाले

पानी के टैंकर ने बाइक सवार मजदूरों को कुचला

मेरठ। मेरठ में हुए दो अलग-अलग हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि कई घायल हो गए। मेरठ के बागपत मार्ग में बुधवार देर रात एक तेज रफ्तार कार बरातियों में घुस गई और पहुंची पुलिस ने को कुचल डाला। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीन से ज्यादा घायल हो गए। वहीं किठौर में पानी के टैंकर की चपेट में आने से बाइक सवार दो मजदूरों की मौत हो गई। वहीं हादसे से गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाबुझाकर शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए।जानकारी के अनुसार मेरठ में बागपत मार्ग पर गांव वाफर में स्थित मंडप के सामने एक कार ने बरातियों को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि तीन घायल हुए हैं।

प्रशासन ने नकल विहीन परीक्षा को लेकर कसी कमर

प्रयाग दर्पण संवाददाता

प्रयागराज। जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री की अध्यक्षता में परिषदीय परीक्षा–2023 (हाईस्कूलइण्टरमीडिएट) को सकुशल, नकल विहीन, निर्विघ्न सम्पन्न कराने के लिए सभी सुपर जोनल, जोनल, सेक्टर, केंद्र व्यवस्थापकों और स्टैटिक मजिस्ट्रेटों के साथ सेंट एंथोनी गर्ल्स इण्टर कालेज में बैठक का आयोजन किया गया। परिषदीय परीक्षा–2023 (हाईस्कूलइण्टरमीडिएट) को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत जनपद में सभी 328 परीक्षा केंद्रों को 25 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। परीक्षा की सुविता के लिए अपर जिलाधिाकारी स्तर के 03 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम स्तर के 08 जोनल मजिस्ट्रेट एवं खण्ड विकास अधिकारी, तहसीलवार सहित 25 सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा सभी परीक्षा केंद्रों पर 01-01 स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं वाह्य केंद्र व्यवस्थापक लगाये गये हैं। जिलाधिाकारी ने कहा कि शासन की मंशा के

निवेश महाकुम्भ के लिए कुम्भ नगरी भी तैयार

प्रयागराज। योगी सरकार को निवेश महाकुम्भ के लिए प्रयागराज में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. लखनऊ में 10 फरवरी को आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सीधा प्रसारण प्रयागराज के जिलाधिकारी कार्यालय के संगम सभागार से होगा। इसमे इस निवेश से जुड़े निवेशक और सम्बंधित दूसरे विभाग के उद्यमी संगठन के लोग मौजूद रहेंगे।योगी सरकार के निवेश महा अभियान में प्रयागराज जनपद से 158 प्रोजेक्ट्स के लिए 53,021 करोड़ रुपये के निवेश के लिए निवेशकों ने अपनी सहमति दी है। डीएम प्रयागराज संजय कुमार खत्री की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक जिले से कुल 278 निवेशकों ने निवेश में अपनी सहमति दी है। इन निवेशकों में 120 निवेशक लखनऊ में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हिस्सा लेने लखनऊ जायेंगे। इन 120 निवेशकों का निवेश में हिस्सा 51,9०8 करोड़ रुपये है।लखनऊ में 10 फरवरी को आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सीधा प्रसारण प्रयागराज में भी होगा। डीएम ऑफिस के संगम सभागार में इसके लाइव प्रसारण की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है। इस प्रसारण में निवेशक , उद्यमी संगठन, सहयोगी विभाग के अधिकारी और एमबीए के छात्र भी हिस्सा लेंगे। संयुक्त उपायुक्त उद्योग लाल जीत सिंह के अनुसार आज तक 70 से अधिक निवेशकों की इसमें शामिल होने की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा संघ से जुड़े 15 उद्यमियों ने भी इसके लिए अपनी सहमति दे दी है। इस आयोजन में इन उद्योगों की स्थापना से सम्बंधित विभागों के 20 अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एमबीए के 10 छात्रों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। इसमें शामिल निवेशकों को यूपी डेस्टिनेशन की बुकलेट, उद्यमी –पुस्तिका और प्रदेश सरकार की निवेश नीति से जुड़े विभिन्न बिन्दुओ का संग्रह भी दिया जाएगा।



व्यक्ति के पास स्वास्थ्य बीमा कार्ड और गैस कनेक्शन होना चाहिये। उन्होंने कहा कि अमृत काल का उद्देश्य भारत के नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाना और गांव-शहरों के बीच के विकास के अन्तार को कम करना है और लोगों की जिन्दगी में सरकार के हस्तक्षेप को कम करना है, इसके अलावा नई तकनीक का स्वागत करना आ रहा है। उन्होंने कहा कि जमाने सात प्राथमिकताओं “सप्तऋषि” में क्रमशः समावेशी विकास, अंतिम छोर-अंतिम व्यक्ति तक पहुँच, बुनियादी ढांचा और निवेश, निहित क्षमताओं का बैंक खाता हो और हर पात्रता वाले

दिव्यांगो को सामजिक सुरक्षा प्रदान करने में प्रयागराज जिले ने दर्ज की बढ़त

प्रयागराज। दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किये गए प्रयासों में प्रयागराज जिले की स्थिति पहले से तेजी से बेहतर हो रही है। दिव्यांगों के मरण पोषण कल्याण के लिए शुरु की गई दिव्यांग भरण– पोषण अनुदान योजना में प्रयागराज अग्रणी है। प्रयागराज जिले में मौजूदा वित्तीय वर्ष में दिव्यांग भरण–पोषण अनुदान योजना में आच्छादित दिव्यांग जनों की संख्या अब तक की सबसे अधिक स्तर तक पहुंच गई है। प्रयागराज के जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी नन्द किशोर याज्ञिक द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक दिव्यांग भरण–पोषण अनुदान योजना के तहत इस वर्ष 29,159 दिव्यांग जन इससे लाभान्वित हुए हैं जो अब तक की जिले में लाभार्थियों की सबसे बड़ी संख्या है। पिछले वित्तीय वर्ष में जनपद में 27,7०9 दिव्यांग जन इसका लाभ पा रहे थे लेकिन इस साल 1448 लाभार्थियों की बढ़ोत्तरी के साथ लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 29,159 पहुंच गई है। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी बताते हैं कि इस सत्यापन के दायरे में ऐसे दिव्यांग आते हैं जिनमें 40 फीसदी से अधिक दिव्यांगता हो। पात्रता के लिए यह भी आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांग की सालाना आय 46,090 रुपये और शहरी क्षेत्र के लिए 56,460 से अधिक न हो। आवेदक विभाग के पोर्टल में इसके लिए आवेदन कर सकता है जिसके सत्यापन के बाद उसे इस पेंशन योजना के तहत 1०00 रुपए की मासिक की पेंशन मिलना शुरु हो जाता है।उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिव्यांग जनों के कल्याण के लिए तत्परता से प्रयास किये हैं. उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी संभालते ही सरकार ने मई 2017 में दिव्यांग भरण पोषण योजना की मासिक अनुदान राशि को 300 से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया। इसके बाद दुबारा इस राशि को बढ़ाकर 1०00 रुपये कर दिया गया: सरकार अब इसे बढ़ाकर 1500 रुपये करने जा रही है।



अनुरुप जनपद में नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन कटिबद्ध हैं। सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी है। शासनादेश में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि जनपद स्तरीय केंद्रीय रूम के माध्यम से सभी परीक्षा केंद्रों की मानीटरिंग की जायेगी। किसी भी स्तर पर किसी के द्वारा किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जायेगी। परीक्षा की सुविता प्रभावित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर

पुलिस कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम को निर्धारित मानकों के अन्तर्गत यदि नहीं मिला तो केन्द्र व्यवस्थापक एवं प्रधानाचार्य सहित सम्बंधित के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। बैठक में पुलिस विभाग की ओर से ए0डी०सी०पी० (अपराध) ने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों सहित आवश्यक पुलिस बल की तैनाती एवं प्रबंध किया गया है। पुलिस परीक्षा कार्य में लगे सभी अधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों की सुरक्षा के प्रति सर्तक है।

स्वत्ताधिकारी मुद्रक, प्रकाशक स्वतंत्र कुमार शुक्ल (यायवल्क्य) द्वारा रमा प्रिंटिंग प्रेस 53/25/1-ए, बेली रोड, नया कटरा, इलाहाबाद से मुद्रित करारकर, 1269 / 1073 मां श्री आश्रम, मालवीय नगर, बाबा जी का बाग, प्रयागराज से प्रकाशित।

—: संस्थापक —:
स्व० श्रीकांत शुक्ल उर्फ स्वामी कांतेश्वरानंद भारती काली बाबा

संपादक
सुतंत्र कुमार शुक्ल (यायवल्क्य)

मोबाइल नंबर 9450475366

Email

prayagdarpan@gmail.com

R.N.I. NO.UPHN/2014/598०4

इस अंक में प्रकाशित समाचारों

के चयन एवं संपादन हेतु पीआरबी

एक्ट के अंतर्गत उत्तरदाई तथा इनसे

उत्पन्न समस्त विवाद इलाहाबाद

न्यायालय के अधीन होंगे।